आकाशवाणी

क्षेत्रीय समाचार

देहरादून (उत्तराखण्ड)

मंगलवार 29.07.2025

समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न; करीब सत्तर प्रतिशत मतदान हुआ।
- केंद्र सरकार, उत्तराखंड को भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराएगी।
- केदारघाटी में हेली सेवाओं की सुरक्षा के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सहस्त्रधारा और सिरसी में सितंबर माह के पहले सप्ताह तक एटीसी स्थापित करने के निर्देश दिए।
- राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज भारी बारिश की चेतावनी, बाढ़ के खतरे के पूर्वानुमान के मद्देनजर जिला प्रशासनों को सतर्क रहने के निर्देश।

पंचायत चुनाव

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ।

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेश के 12 जिलों के 40 विकासखंडों की ग्राम पंचायतों में हुए मतदान में लगभग सत्तर प्रतिशत मतदान हुआ है। इसमें पैंसठ दशमलव पांच प्रतिशत पुरुष और चौहत्तर दशमलव पांच प्रतिशत महिलांए शामिल हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के प्रशासन और पुलिस द्वारा चुनाव संपन्न कराने में दिए गए सहयोग की सराहना की।

गौरतलब है कि राज्य के 12 जिलों के नवासी विकासखंडों में दो चरणों में पंचायत चुनाव कराए गए। मतगणना 31 जुलाई को होगी।

अतिरिक्त धनराशि

उत्तराखंड को भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार से अतिरिक्त धनराशि मिलेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर कहा कि उत्तराखंड में इस योजना का काम तेज गति से हो रहा है और इसके लिए आगे भी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राज्य में पहले चरण में पांच गांवों में भूमि सर्वेक्षण और पुनः सर्वेक्षण का परीक्षण किया जाएगा। परिणाम संतोषजनक आने पर पूरे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रक्रिया लागू की जाएगी तथा इसके लिए और धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। तहसील स्तर पर बनाए जा रहे आधुनिक अभिलेख कक्षों के निर्माण की बकाया राशि भी जल्द जारी की जाएगी।

मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड आधुनिक और पारदर्शी भूमि प्रबंधन प्रणाली विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। लिडार जैसी आधुनिक तकनीक से भूमि सर्वेक्षण किया जा रहा है और भू–अभिलेखों का डिजिटलीकरण समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है।

कार्रवाई

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर गैर–पंजीकृत और मानकों से नीचे चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों पर सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रणनीति बनाते हुए राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और एसटीएफ के साथ मिलकर अभियान तेज कर दिया है।

राज्य में कई नशा मुक्ति केंद्र बिना पंजीकरण और निर्धारित मानकों के संचालन कर रहे हैं। ऐसे केंद्रों की पहचान कर उन्हें बंद करने और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। प्रत्येक जिले में औचक निरीक्षण बढ़ाए जाएंगे और एसटीएफ, निरीक्षण टीमों को सहयोग देगी।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और पुनर्वास केंद्रों की गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा। सभी केंद्र केवल शेल्टर होम न रहकर पूर्ण पुनर्वास की दिशा में काम करें, यह सुनिश्चित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्वास्थ्य और पुलिस विभाग मिलकर नशा मुक्ति केंद्रों को मानकों के अनुरूप और जवाबदेह बनाने पर काम कर रहे हैं। यह अभियान निरीक्षण तक सीमित न रहकर कठोर प्रशासनिक फैसलों के साथ आगे बढ़ेगा, ताकि नशा मुक्ति की आड़ में हो रही अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सके।

हॉउस ऑफ हिमालयाज़

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में हाउस ऑफ हिमालयाज़ की 5वीं बोर्ड बैठक हुई, जिसमें नए उत्पादों की समीक्षा और वैश्विक विस्तार की रणनीति पर चर्चा की गई।

मुख्य सचिव ने कहा कि उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखना और जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण अनिवार्य है। उन्होंने जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार–प्रसार और उत्पादों में क्यूआर कोड के माध्यम से ट्रेसिबिलिटी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

बैठक में बताया गया कि दिसंबर 2023 लॉन्च हाउस ऑफ हिमालयाज़ ने अब तक 2 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री की है, जिससे 3 हजार से अधिक महिलाओं को रोजगार मिला है। कंपनी के आउटलेट जौलीग्रांट एयरपोर्ट सहित 26 मुख्य स्थानों पर मौजूद हैं।

50 से अधिक प्राकृतिक, हर्बल और जैविक उत्पादों के साथ कंपनी आने वाले समय में दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित अन्य राज्यों में विस्तार और अमेरिका, यूएई, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में प्रवेश की योजना बना रही है। साथ ही 2025–26 में 10 करोड़ और 2026–27 में 25 करोड़ रुपये की बिक्री का लक्ष्य रखा है।

हेली सेवा बैठक

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में केदार घाटी में हेली सेवाओं की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर बैठक की। उन्होंने युकाडा और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों को सहस्त्रधारा और सिरसी में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सितंबर के पहले सप्ताह तक स्थापित करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक हेलीपैड पर हेलीपैड–इन–चार्ज की तैनाती की जाए और शटल सेवाओं की समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। हेलीपैड संचालन के लिए एसओपी का पूर्ण पालन अनिवार्य होगा। प्रत्येक उड़ान का समय और उड़ान संख्या बोर्डिंग पास पर दर्ज की जाएगी।

उन्होंने निर्देश दिए कि हेली कंपनियां नियमों का पालन करें और मौसम विभाग से मौसम की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए मौसम अधिकारी की व्यवस्था की जाएगी, जिसकी लागत युकाडा वहन करेगा।

मौसम

प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कल रात से ही रूक–रूककर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का यह दौर जारी रहेगा। विभाग ने आज राजधानी देहरादून सहित पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अतिरिक्त, राज्य के अन्य हिस्सों में भी बारिश की चेतावनी दी गई है।

भारी बारिश के मद्देनज़र आम लोगों से सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

इस बीच, बारिश की चेतावनी के चलते अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी जिलों में निम्न से मध्यम स्तर के बाढ़ के खतरे का पूर्वानुमान है। इसके मद्देनजर, राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र, देहरादून ने इन सभी जिलों के जिलाधिकारियों को अपने–अपने क्षेत्रों में सावधानी बरतने की सलाह दी है।

पौधरोपण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी स्थित एफटीआई परिसर में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधारोपण किया और लोगों से प्रकृति संरक्षण में सहभागिता की अपील की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान पर्यावरण संरक्षण का प्रेरणादायक प्रयास है। उन्होंने लोगों से इस पवित्र सावन माह में एक पेड़ लगाकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया।

मनसा देवी मंदिर हादसे पर मुख्यमंत्री ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए श्री धामी ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए राज्य सरकार ने आवश्यक कदम उठाए हैं। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर व्यवस्थाएं मजबूत की जा रही हैं, जिनमें केयरिंग कैपेसिटी के अनुसार प्रवेश, स्थान का विस्तार, पार्किंग और सुरक्षा मानकों का पालन शामिल है।

मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण पर भी सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जों की पहचान कर उन्हें हटाया जाएगा, ताकि सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा और विकास कार्यों की गति सुनिश्चित हो सके।

जागरूकता गोष्ठी

विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर पौड़ी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, खिर्सू में स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में जनजागरुकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर जीशान अली ने लोगों को हेपेटाइटिस रोग के लक्षण, प्रभाव और बचाव के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हेपेटाइटिस एक विषाणु जनित रोग है, जो मुख्य रूप से यकृत को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि हेपेटाइटिस बी और सी लंबे समय तक इलाज न होने पर लीवर कैंसर जैसी घातक बीमारी का कारण बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि साफ–सफाई, स्वच्छ खान–पान और टीकाकरण से इस बीमारी से बचा जा सकता है।

एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर

लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा की खबर सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। दैनिक जागरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखता है– मुंबई आतंकी हमले के बाद होती कार्रवाई तो पहलगाम की हिम्मत नहीं करता पाक। इसी पर राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र की सुर्खी है– गिड़गिड़ाया था पाकिस्तान। हिंदुस्तान लिखता है– ऑपरेशन सिंदूर पर संसद गर्म।

पंचायत चुनाव में दूसरे चरण के मतदान की ख़बर सभी समाचार पत्रों की सुर्खियों में है। अमर उजाला का शीर्षक है– दूसरे चरण में बारिश के बीच जमकर बरसे वोट। इसी पर दैनिक जागरण लिखता है– पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में भी जबरदस्त उत्साह। नवोदय टाइम्स का शीर्षक है– मतदान निपटा, अब 31 का इंतजार।

उत्तराखंड में धर्मांतरण संबंधी हालिया गतिविधियों को देखते हुए प्रदेश सरकार से सख्त रूप अपनाया है। नवोदय टाइम्स का शीर्षक है– और सख्त होगा उत्तराखंड का धर्मांतरण कानून। इसी पर अमर उजाला मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है– ऑपरेशन कालनेमि के लिए गठित की जाएगी एसआईटी।

एक अन्य ख़बर पर हिंदुस्तान समाचार पत्र का शीर्षक है– उत्तराखंड के मंदिरों में प्रवेश के मानक बदले जाएंगे। नवोदय टाइम्स लिखता है– सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों में लागू होगी पंजीकरण व्यवस्था। राष्ट्रीय सहारा मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है– प्रसिद्ध मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए समुचित व्यवस्थां बनाएं।